सी.आई.टी.यू. के 40 वर्ष

एम.के.पंधे

सी.आई.टी.यू. प्रकाशन

सीटू के 40 साल

एम के पंधे

सीआईटीयू प्रकाशन

सीटू के 40 साल

30 मई 2010 को सीटू अपनी मौजूदगी के 40 साल पूरे करने जा रही है। हिन्दुस्तान के मजदूर आन्दोलन में सीटू की भूमिका आरम्भ से ही अद्वितीय रही है। सीटू ने आम आदमी और मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए हमेशा ही वर्ग संघर्ष की अवधारणा की तरफदारी की है।

पृष्ठभूमि

सीटू का उद्‌भव ऐसे दौर में हुआ जब ट्रेड यूनियन आन्दोलन में इस विषय पर गहरी बहस चल रही थी कि देश के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक परिदृश्य में मजदूर आन्दोलन की क्या भूमिका है? साठ के दशक के दौरान आने वाले भारी आर्थिक संकट को पूरी तरह से मजदूर वर्ग पर थोप दिया गया। इसके परिणामस्वरुप आम आदमी में गहराते असंतोष को उस जगह पहुँचा दिया जहाँ केन्द्र और अधिकांश राज्य सरकारों पर काबिज शासक पार्टी कॉंग्रेस को परिस्थिति ने आम जनता से अलग–थलग कर दिया। छठे दशक के मध्य के बाद उसे बहुत सी राज्य सरकारों से उखाड़ फेंका गया। कुल मिलाकर देश के राजनैतिक परिदृष्य में विक्षोभ की स्थिति पैदा हो गयी।

वर्ग संघर्ष को नज़रअन्दाज किया

सीटू की स्थापना के 40 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह आवश्यक हो जाता है कि हम उस पृष्ठभूमि पर भी नजर डालें जिसमें सीटू की स्थापना हुई। साथ ही साथ यह समझना भी आवश्यक है कि उस समय ट्रेड यूनियन आन्दोलन के नेताओं की वर्ग सहयोग की भूमिका ने ऐसे हालात पैदा क़र दिए थे कि एटक से अलग होकर वर्ग संघर्ष को नेतृत्व प्रदान किया जा सके। वर्ग संघर्ष की नीति पर चलने का यह प्रावधान सीटू के संविधान में स्पष्ट रुप से किया गया है।

आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में आम आदमी और मेहनतकशों के जीवन यापन पर हमले किए जा रहे थे, ये हमले कारखाना बन्दी, ठेकेदारी बढ़ाकर, बेरोजगार करके और श्रमिकों से सामाजिक सुरक्षा एवं

सामूहिक सौदेबाजी और बोनस के अधिकार आदि को छीन कर किए जा रहे थे। मजदूर वर्ग पर ऐसे हमलों के बावजूद भी अधिकांश स्थापित केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों का रवैया बहुत ही लचर बना हुआ था। सरकार की नीतियों के तहत मजदूर वर्ग पर होने वाले इन हमलों के विरुद्ध संयुक्त संघर्षों का कोई प्रयास नहीं था।

इस काम में प्रमुख भूमिका निभाने की उम्मीद लाल झण्डे के एटक जैसे संगठनों से ही की जा सकती थी कि वह इन हमलों और उसके लिए जिम्मेदार केन्द्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध मजदूर वर्ग के सभी हिस्सों को लामबन्द करके संयुक्त संघर्ष चलाए। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा कतई नहीं हो रहा था। बल्कि एस.ए. डाँगे के नेतृत्व में काबिज नेता दो खम्भों नामक नीति के तहत वर्ग संघर्ष के बजाय वर्ग सहयोग पर चल रहे थे। और शासक वर्गों एवं शासक पार्टी की नीतियों के साथ इस वर्ग सहयोग को भी प्रगतिशीलता से जोड़ कर पेश किया जा रहा था। नेताओं के इस वर्ग द्वारा सहयोगवादी गुट के द्वारा वर्ग संघर्ष के विचार की ही खिल्ली उड़ायी जा रही थी। देश के ट्रेड यूनियन आन्दोलन में वामपन्थी ट्रेड यूनियनें नेतृत्वकारी भूमिका में रही है। परन्तु एस.ए. डाँगे के नेतृत्व वाले गुट के द्वारा सुधारवादी नीतियों पर चलने के कारण धीरे–धीरे वामपन्थी ट्रेड यूनियनें अपनी नेतृत्वकारी भूमिका से हाथ धो बैठीं।

संगठन में दुरुस्तीकरण दुःश्वार

एटक में उस समय अनेक नेता ऐसे थे जो राष्ट्रीय स्तर और उद्योग स्तर पर वर्ग संघर्ष की नीतियों पर चलते हुए सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के विरुद्ध जमकर संघर्ष करते हुए मजदूर आन्दोलन को ठीक रास्ते पर लाने का भरसक प्रयास कर रहे थे। उन्होने संगठन के आन्तरिक जनवाद की सीमा में और संगठन की एकता को कायम रखते हुए भरसक प्रयास किया कि संगठन वर्ग संघर्ष की नीतियों पर चलते हुए देश के पैमाने पर संघर्ष चलाए। लेकिन एटक के तात्कालिक नेता जो कि एस.ए. डाँगे के प्रभाव में थे, और उनकी गैर जनवादी सोच एवं व्यवहार ने संगठन के अन्दर बहस–मुबाहिसे मतभेदों को दूर करने का कोई मौका ही नहीं दिया। हद तो यहाँ तक हो गयी कि जो यूनियनें वर्ग

संघर्ष के रास्ते पर थीं उन्हे सम्बद्धता तक देने से इन्कार कर दिया गया ताकि संगठन को तात्कालिक सुधारवादी नेतृत्व की गिरफ्त में ही बनाए रखा जा सके।

एकता के प्रयास

देश के अधिकांश केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के नेताओं के वर्ग संघर्ष विरोधी चरित्र के बावजूद भी विभिन्न क्षेत्रों के मजदूरों द्वारा जमीनी स्तर पर वर्ग संघर्ष जारी रहा। छठे दशक के मध्य से लेकर स्टील, जूट, ट्रान्सपोर्ट, कोयला खदान, कपड़ा उद्योग और अन्य उद्योगों में बड़े–बड़े संघर्ष, मजदूरों के अधिकारों पर होने वाले हमलों और क्लोजर, मिल बन्दी आदि के खिलाफ होते रहे। इन बड़े–बड़े संघर्षों की पृष्ठभूमि में सीटू का उद्‌भव हुआ, जैसा कि सीटू के स्थापना सम्मेलन में प्रस्तुत रिपोर्ट में का० पी. राममूर्ति की रिपोर्ट में काफी विस्तार से वर्णन किया गया है।

एटक के तात्कालिक संघर्षशील नेताओं जैसे बी.टी. रणदिवे, ज्योति बसु और पी. राममूर्ति आदि ने एक दशक तक, शासक वर्गों की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष की धार तेज बनाए रखी। अन्ततः यह महसूस किया गया कि शासक वर्गों की मजदूर विरोधी नीतियाँ जैसे वेतन में कटौती, बोनस और महँगाई भत्ते के भुगतान से इन्कार, गैर कानूनी तरीकों से क्लोजर, लॉक–आऊट, ले–ऑफ आदि के खिलाफ होने वाले प्लान्ट स्तर के संघर्षों को देश के स्तर पर विस्तार दिया जाए।

केवल संघर्षों के लिए एकता

एकता महज नाम मात्र की एकता नहीं, अथवा सिर्फ नेताओं की एकता ही नहीं, बल्कि शासक वर्गों की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध आम मजदूरों की एकता ही मजदूर आन्दोलन का प्रमुख कार्य है। मजदूर वर्ग पर होने वाले घातक हमलों और शोषण के खिलाफ वर्ग संघर्ष का रास्ता न पकड़ने से न सिर्फ मजदूर आन्दोलन, बल्कि जनवादी आन्दोलन को भी भारी नुकसान पहुँचता है।

विशुद्ध रुप में इसी समझदारी के साथ सीटू का गठन किया

गया। 9–10 अप्रैल 1970 को गोवा में आयोजित मजदूरों के सम्मेलन में इस मुद्दे पर काफी विस्तार से चर्चा हुई कि एकता को बनाए रखकर संगठन को वर्ग संघर्ष की राह पर लाने के तमाम प्रयास असफल रहे हैं, क्योंकि एस.ए. डाँगे के नेतृत्व वाले सुधारवादी नेताओं की वर्ग सहयोगवादी नीतियों के कारण संगठन को वर्ग संघर्ष के रास्ते पर लाना बहुत मुश्किल है। अतः शासक वर्गों की मजदूर विरोधी नीतियों के विरुद्ध वर्ग संघर्षों को देश के पैमाने पर तेज करने के लिए एक नए केन्द्रीय मजदूर संघ के निर्माण की आवश्यकता महसूस की गयी, ताकि देश के मजदूर आन्दोलन को सही दिशा दी जा सके। और इस सम्मेलन में इस आशय का एक प्रस्ताव पास भी किया गया।

सीटू का स्थापना सम्मेलन

गोवा सम्मेलन में पास हुए प्रस्ताव पर आगे काम करते हुए सीटू का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन कलकत्ता में 27–31 मई 1970 को बुलाया गया। एटक की राज्य ईकाई बंगाल प्रोविजनल ट्रेड यूनियन काँग्रेस (बी.पी.टी.यू.सी.) ने अखिल भारतीय सम्मेलन को सफल बनाने में अथक प्रयास किए। का० ज्योति बसु के नेतृत्व में एक स्वागत समिति बनायी गयी जिसने सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जबरदस्त तैयारियाँ की। का० बी.टी. रणदिवे ने अपने उद्घाटन भाषण में विस्तार से बताया कि मजदूर आन्दोलन के समक्ष जो चुनौतियाँ मौजूद हैं, उनका मुकाबला वर्ग संघर्ष के रास्ते पर चलकर ही किया जा सकता है। का० पी. राममूर्ति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि एटक में रहकर लगातार 6 वर्ष तक मजदूर आन्दोलन की एकता बनाए रखने के अनथक प्रयास करने के बावजूद भी वर्ग संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए असफलता ही हाथ लगी। और 30 मई 1970 को पूरे जोशो–खरोश एवं खुशी के साथ बाकायदा एक प्रस्ताव पास करके का० बी.टी. रणदिवे को अध्यक्ष और का० पी. राममूर्ति को महासचिव चुनते हुए एक नए ट्रेड यूनियन संगठन के रुप में सीटू के गठन की घोषणा की गयी। और एक क्रान्तिकारी ट्रेड यूनियन संघ की स्थापना की खुशी मनाने के लिए कलकत्ता के ब्रिगेड परेड ग्राऊण्ड में मजदूरों की बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया।

सीटू का संविधान

सीटू के संविधान में अपने उद्देश्य और लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए निम्न प्रकार कहा गया है कि:–

"सीटू का यह दृढ़ विश्वास है कि मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्ति दिलाने का एक मात्र रास्ता है कि समाज के उत्पादन के साधनों, वितरण एवं विनिमय का सामाजीकरण करने के लिए समाजवादी राज्य की स्थापना की जाए। समाजवाद के आदर्शों को केन्द्र में रखकर सीटू सभी प्रकार के शोषण से मुक्त समाज के निर्माण के लिए कटिबद्ध है" . . . और

"सीटू का दृढ़ विश्वास है कि वर्ग संघर्श के बिना कोई सामाजिक बदलाव संभव ही नहीं है, इसलिए सीटू मजदूर वर्ग को वर्ग सहयोगवादी रास्ते से हटाने का प्रयास लगातार करता रहेगा।"

सीटू पर हमला

सीटू की स्थापना के तुरन्त बाद से उसे सरकार के दमनकारी हमलों और ट्रेड यूनियनों के हिस्से के द्वारा सीटू को अलग–थलग करने के प्रयासों का सामना करना पड़ा। इस सबके बावजूद भी सीटू अपने वर्ग संघर्ष के रास्ते पर दृढ़ रहकर मजदूर वर्ग का रहनुमा अग्रणी संगठन बन गया। पूँजीवादी शोषण पर आधारित समाज व्यवस्था को बदल डालने की वकालत करते हुए सीटू ने समाजवादी समाज की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया। और वर्तमान समाज व्यवस्था को बदलकर समाजवादी समाज की स्थापना के द्वारा ही मजदूर वर्ग के लिए काम और जिन्दगी के हालातों में परिवर्तन संभव हो सकता है तथा अमानवीय शोषण से मुक्ति मिल सकती है। सीटू ने मजदूर वर्ग से राजनैतिक आन्दोलन में भाग लेने का आह्वान किया है, ताकि कॉरपोरेट सैक्टर द्वारा आम जनता की लूट–खसोट के द्वारा बेशुमार मुनाफा कमाने की नीयत पर ट्रेड यूनियन आन्दोलन असरदार ढंग से रोक लगा सके।

सीटू की स्थापना के तुरन्त बाद सबसे बड़ा हमला दुर्गापुर में स्टील मजदूरों पर हुआ और दुर्गापुर स्टील प्लान्ट और एलॉय स्टील

प्लान्ट के मजदूरों ने सीटू नेतृत्व में एक लम्बा संघर्ष चलाया। इस संघर्ष में इन मजदूरों ने बहुत ही बहादुरी से जानलेवा हमलों का मुकाबला करते हुए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। सीटू ने दुर्गापुर के मजदूरों के समर्थन में देशव्यापी एकजुट कार्यवाहियाँ आयोजित कीं।

शासक वर्गों ने सीटू को देश के मजदूर आन्दोलन से अलग–थलग करने में अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं रखी। भारत सरकार की कृपा पर नेशनल कौन्सिल ऑफ ट्रेड यूनियन्स (NCTU) का गठन करने के इरादे से 1971 में तत्कालीन केन्द्रीय श्रम मंत्री श्री आर.के. खादिलकर द्वारा बुलायी गयी मीटिंग में इन्टक, एटक और एच.एम.एस. ने भाग लिया। इस नेशनल कौन्सिल ऑफ ट्रेड यूनियन्स (NCTU) ने केन्द्र में बैठी काँग्रेस सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों को समर्थन करना शुरु किया। शासक वर्गों के द्वारा सरकार समर्थक एवं सरकार विरोधी दो गुटों में मजदूर आन्दोलन को बाँटकर असली मुद्दों से मजदूर आन्दोलन का ध्यान हटाने की इस खतरनाक मुहिम गम्भीरता से समझते हुए सीटू ने पहल करके अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियन्स यू.टी.यू.सी., यू.टी.यू.सी. (एल. एस.) एवं जॉर्ज फर्नाडीस के नेतृत्व वाले एच.एम.के.पी. और औद्योगिक महासंघों, इन्श्योरेन्स एवं केन्द्रीय कर्मचारियों के महासंघों जैसे अन्य संगठनों को साथ लेकर यूनाईटेड कॉन्सिल ऑफ ट्रेड यूनियन्स (UCTU) नामक एक साझा मंच तैयार किया। ताकि संयुक्त संघर्षों के द्वारा मजदूरों की हितों की रक्षा की जा सके। यूनाईटेड कॉन्सिल ऑफ ट्रेड यूनियन्स (UCTU) ने मजदूरों के अनेक मुद्दों के लिए अखिल भारतीय संघर्ष छेड़ा और बाद में काँग्रेस सरकार द्वारा देश की जनता पर थोपे गए अनुचित आपातकाल के विरुद्ध जमकर संघर्ष किया। इस दौरान अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे उभर कर सामने आए। इन मुद्दों में से एक था कम्प्लसरी डिपोजिट स्कीम (सी.डी.एस.) जो मजदूरों के बीच इन्दिरा फण्ड के नाम से जाना जाता था, जिसके तहत मजदूरों को बढ़ा हुआ मँहगाई भत्ता देने के बजाय पी.एफ. में जमा करने का प्रावधान सरकार ने जबरन थोप दिया। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था वेतन जाम जिसे भारत सरकार ने डा० सुखमय चक्रवर्ती कमेटी की सिफारिशों पर लागू किया। नेशनल कौन्सिल ऑफ ट्रेड यूनियन्स (NCTU) ने केन्द्र सरकार की इन दोनों ही मुहिमों का समर्थन किया और यूनाईटेड कॉन्सिल ऑफ ट्रेड यूनियन्स (UCTU) ने इसके विरोध में देशव्यापी संघर्ष चलाया और

मजदूरों के बीच इस संघर्ष को सम्बद्धता से ऊपर उठकर जबरदस्त समर्थन मिला। इस दौरान सरकार समर्थक नेशनल कौन्सिल ऑफ ट्रेड यूनियन्स (NCTU) निष्क्रिय हो गया और बाद में एच.एम.एस. ने खुद को औपचारिक रुप से उससे अलग कर लिया।

सीटू के जन्म के बाद के दौर में 1974 में रेलकर्मियों की बहादुराना 20 दिन तक चली हड़ताल संयुक्त संघर्ष की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके दौरान सरकार के तमाम दमन, उत्पीड़न और जुल्मो–सितम का रेलवे के मजदूरों ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसने तकरीबन सभी ट्रेड यूनियन संघों को देशव्यापी आन्दोलनों के सही रास्ते पर ला दिया। नेशनल कौन्सिल ऑफ ट्रेड यूनियन्स (NCTU) की सरकार समर्थक दृष्टिकोण का पर्दाफाश हो चुका था। एक समय ऐसा आया कि नेशनल कोऑर्डीनेशन कमेटी फॉर रेलवेमैन्स स्ट्रगल (NCCRS) रेलवे मजदूरों को सबसे बड़ा मंच बनकर उभरा जिसने इन्टक को छोड़कर तकरीबन सभी ट्रेड यूनियन महासंघों को संयुक्त संघर्ष के लिए एक मंच पर ला दिया। रेलवे के हड़ताली मजदूरों की एकजुटता में कार्यवाही करने में सीटू ने अग्रणी भूमिका अदा की। और प्रताड़ित रेलवे मजदूरों को अन्य प्रकार की राहतों के साथ–साथ सर्वाधिक कानूनी मदद पहुँचाने में भी सीटू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। 1974 की रेलवे की हड़ताल ने मजदूरों के सम्बद्धता से ऊपर उठकर समूचे मजदूर आन्दोलन को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की बल्कि उसके बाद के राजनैतिक विकास की दिशा भी तय की।

आपातकाल के दिनों में

इन्दिरा गान्धी सरकार द्वारा पूँजीवाद समर्थक नीतियाँ अपनाने के कारण और आम आदमी के सामने उपजे गम्भीर आर्थिक संकट के कारण उन दिनों इन्दिरा गान्धी सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरुद्ध काफी तेज और लम्बे संघर्ष चल रहे थे।

अपनी ही सरकार की अस्थिरता का सामना कर रही श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। विरोधी राजनैतिक दलों के अनेक नेताओं को गिरफ्तार करके बिना

किसी न्यायिक कार्यवाही के ही जेल में डाल दिया गया। ट्रेड यूनियन आन्दोलन को भी कुचला गया और देश में किसी भी प्रकार की कार्यवाहियाँ आयोजित करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गयी। समाचार पत्र–पत्रिकाओं पर सख्त सेन्सरशिप थोप दी गयी। सरकारी अधिकारियों की इजाजत के बिना कोई भी लेख अखबारों में छापने की अनुमति नहीं थी। संगठन बनाने की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर अंर्तराष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रस्तावों को छापने के लिए सीटू को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। क्योंकि सरकारी अधिकारी ने 1930 में लिखे गए दिमित्रोव के एक लेख को भी छापने से मना कर दिया। और यह न्यायालय के आदेश पर ही छापा जा सका।

आपात काल का सहारा लेकर सरकार बोनस भुगतान की न्यूनतम सीमा को 8.33 प्रतिशत से घटाकर मात्र 4 प्रतिशत करने का एक बिल संसद में लेकर आयी। सीटू ने इस बिल का जमकर विरोध किया और हमारे सांसदों ने संसद में अपना विरोध दर्ज कराया। आपात काल के विरोध में श्री जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में चलने वाले जन आन्दोलन को बड़े पैमाने पर सक्रिय समर्थन किया।

आपात काल में हड़ताल पर सख्त रोक लगा दी गयी थी। यहाँ तक कि ट्रेड यूनियन आन्दोलन की वैधानिक कार्यवाहियों को भी प्रतिबन्धित कर दिया गया। सीटू ने भारत सरकार द्वारा ट्रेड़ यूनियन गतिविधियों पर रोक लगाने की शिकायत अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन के समक्ष दर्ज करायी। अनेक उद्योगों में मजदूरों पर वेतनजाम थोप दिया गया। आवश्यक वस्तुओं के दामों में भारी वृद्धि के बावजूद भी भारत सरकार ने वेतन वृद्धि की इजाजत नहीं दी।

1977 में भारत सरकार को आपातकाल वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया गया, चुनावों में इंदिरा गांधी की सरकार की करारी हार हुई और स्वतंत्र भारत में श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली गैर–काँग्रेसी सरकार गठित हुई। श्रीमती इन्दिरा गान्धी स्वयं भी चुनाव हार गयी। इस प्रकार जनता ने आपात काल के विरुद्ध अपना मत प्रकट किया और इस नयी राजनैतिक परिस्थिति का सीटू ने स्वागत किया।

आपात काल के तमाम प्रतिबन्धों के बावजूद भी सीटू और अन्य ट्रेड यूनियन संगठनों की ताकत में अच्छी खासी वृद्धि हुई। आपात काल की समाप्ति ट्रेड यूनियन आन्दोलन के इतिहास में शर्मनाक

अध्याय की समाप्ति रही।

संयुक्त संघर्षों के बारे में

सीटू के जन्म के बाद में ट्रेड यूनियन आन्दोलन को संगठित करने प्रयासों के दौरान अनेक प्रकार के दौर से गुजरना पड़ा है। और आने वाले हर एक दौर में एकता की छतरी लगातार बढ़ती ही चली गयी। पहला दौर था यूनाईटेड कॉन्सिल ऑफ ट्रेड यूनियन्स (UCTU) का जो इन्टक के नेतृत्व में बड़े ट्रेड यूनियनों के सरकार समर्थक गुट के दौर में आया। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार के समय औद्योगिक सम्बन्ध बिल 1978 के ऊपर सभी ट्रेड यूनियन संगठनों को कुछ समय के लिए ही सही परन्तु एक मंच पर ला दिया। उसके बाद 1981 में इन्टक को छोड़कर सभी केन्द्रीय श्रम संघों और औद्योगिक महासंघों को नेशनल कैम्पेन कमेटी के मंच पर ला कर खड़ा कर दिया। उसके बाद के दौर ने सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों को राष्ट्रव्यापी स्तर पर एकजुट कर दिया। नब्बे के दशक में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के खिलाफ अभियान और संघर्ष चलाने के लिए स्पोन्सिरिंग कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन्स का गठन हुआ, जिसमें सभी प्रमुख केन्द्रीय श्रम संघों के साथ ही साथ उद्योगों एवं सेवा क्षेत्र के उद्योगवार स्वतंत्र अखिल भारतीय महासंघों को एक मंच पर ला दिया। आज के दौर में इन्टक एवं बी.एम.एस. को शामिल करते हुए हमें और अधिक व्यापक एकता देखने को मिल रही है।

सीटू के गठन के बाद से संयुक्त संघर्षों को, सरकार की नीतियों के विरोध के रणनीतिक रास्ते पर लाया जा सका है। औद्योगिक सम्बन्ध बिल 1978 के विरुद्ध सभी ट्रेड यूनियन संगठनों ने पूरे देश के स्तर पर भारी विरोध किया और इस व्यापक मंच पर एटक, इन्टक और बी.एम.एस. भी आ गए। और परिणाम स्वरुप सरकार को वह बिल कूड़ेदान में फेंकना पड़ा।

नेशनल कैम्पेन कमेटी

केन्द्र में काँग्रेस के पुनः सत्ता पर काबिज होते ही इन्टक संयुक्त मंच से

अलग हो गयी, लेकिन मजदूरों के साझा संघर्षों के मंच का विस्तार करने के प्रयास जारी ही रहे। नेशनल कैम्पेन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन्स (NCC) का गठन जून 1981 में मुम्बई में आयोजित अखिल भारतीय सम्मेलन में किया गया, जिसमें इन्टक को छोड़कर सभी केन्द्रीय श्रम संगठन और अनेक औद्योगिक महासंघ भी शामिल हुए। इस अभियान समिति ने मजदूर वर्ग के अधिकारों पर होने वाले अनेक हमलों के खिलाफ संघर्ष चलाया। राष्ट्रीय अभियान समिति के आह्वान पर 19 जनवरी 1982 को एक दिन की ऐतिहासिक आम हड़ताल एक शानदार सफल कार्यवाही रही है। यह भारत के राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन आन्दोलन के इतिहास में मजदूर वर्ग की पहली राष्ट्रव्यापी शक्तिशाली हड़ताली कार्यवाही रही। इस अवसर पर सीटू के तत्कालीन अध्यक्ष का० बी.टी. रणदिवे और महासचिव का० पी राममूर्ति ने संयुक्त वक्तव्य में मजदूर वर्ग को बधाई देते हुए कहा कि "काँग्रेस शासित राज्यों में 50000 से अधिक मजदूरों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गिरफ्तार करने, पुलिस द्वारा लाठी चार्ज और गोलीबारी करने और भाड़े के गुण्डों के जान लेवा हमलों जिनमें कई मजदूरों के मारे जाने जैसी क्रूर कार्यवहियों के बावजूद भी लाखों मजदूर हड़ताल करके सड़कों पर उतर कर हिन्दुस्तान के मजदूर आन्दोलन में इतिहास कायम किया है।

कमेटी ऑफ पब्लिक सैक्टर ट्रेड यूनियन्स (CPSTU)

देश के मजदूर आन्दोलन में सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों की बहुत ही अहम् भूमिका रही है। राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग रणनीतिक महत्व रखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की यूनियनों को एक संयुक्त संघर्ष के मंच पर लाने में सीटू की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रही है। सीटू ने देशव्यापी अभियान चलाकर सार्वजनिक क्षेत्र को बदनाम करने वाली सरकार की मुहिम का पर्दाफाश किया। श्रीमती इन्दिरा गान्धी द्वारा गठित डा० अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी की गुप्त रिपोर्ट का खुलासा करते हुए यह रिपोर्ट छापकर देश के सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों में प्रसारित की। इस गुप्त रिपोर्ट में सार्वजनिक क्षेत्र को बदनाम करके समाप्त कर देने की साजिश की योजना सिफारिशों के रुप में पेश की गयी हैं। सरकार की साजिश के खिलाफ चलाए गए अभियान और अनेक

सार्वजनिक उपक्रमों में चलने वाले संघर्षों के मद्देनजर यह आवश्यक हो गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र की यूनियनों की कमेटी CPSTU का गठन किया जाए। 1985 में सीटू से सम्बद्ध और दोस्ताना सार्वजनिक क्षेत्र की यूनियनों का एक बड़ा सम्मेलन बंगलौर में आयोजित करके यह निर्णय लिया गया कि ऑल इण्डिया कोओर्डीनेशन कमेटी ऑफ पब्लिक सैक्टर ट्रेड यूनियन्स के गठन करने का सिद्धान्ततः निर्णय लिया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता सीटू के अध्यक्ष का० बी.टी. रणदिवे ने की और इस सम्मेलन में का० पी राममूर्ति और का० समर मुखर्जी ने भी भाग लिया। इसके बाद दुर्गापुर स्टील टाऊनशिप में एक सम्मेलन करके बाकायदा एक ऑल इण्डिया कोओर्डीनेशन कमेटी ऑफ पब्लिक सैक्टर ट्रेड यूनियन्स का गठन औपचारिक रुप से किया गया। इस कमेटी ने पहल करके सार्वजनिक क्षेत्र की यूनियनों के व्यापक मंच के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वर्ष 1986 में हैदराबाद में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें प्रमुख केन्द्रीय श्रम संघों से सम्बद्ध यूनियनों और ज्वाइन्ट एक्शन फ्रन्ट बंगलौर तथा पब्लिक सैक्टरर्स कोओर्डीनेशन कमेटी हैदराबाद से जुड़ी यूनियनें बड़ी तादाद में शामिल हुई। उसके बाद से CPSTU सार्वजनिक क्षेत्र की यूनियनों का संयुक्त मंच बन गया, जिसकी पहचान सार्वजनिक क्षेत्र और उसके मजदूरों के अधिकारों की रक्षा का अग्रणी रहनुमा बन गया।

स्पोन्सरिंग कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन्स

देश के शासक वर्गों ने अर्थ नीति के मामले में 1991 से आत्मनिर्भरता का रास्ता छोड़कर नव उदारवादी वैश्वीकरण का दक्षिणपन्थी रुझान पकड़ लिया है। भारत सरकार ने 1991 से विश्व बैंक और अर्न्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशों को अपनाते हुए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) की देश विरोधी जन विरोधी घातक नीतियों को अपना लिया। इस प्रकार संयुक्त रुप से संगठित मजदूर आन्दोलन के समक्ष नयी परिस्थितियाँ पैदा हो गयी। इन्टक और बी.एम.एस. ने स्वयं संयुक्त आन्दोलन से अलग ही रखा और शेष सभी केन्द्रीय श्रम संघों ने संयुक्त रुप से सरकार की LPG नीतियों के विरोध में 29 नवम्बर 1991 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इससे स्पोन्सरिंग कमेटी ऑफ

ट्रेड यूनियन्स के गठन का रास्ता तैयार हुआ। इन्टक और बी.एम.एस. को छोड़कर शेष सभी केन्द्रीय श्रम संघों और उद्योगों एवं सेवा क्षेत्र के उद्योगवार अन्य स्वतंत्र अखिल भारतीय महासंघों, केन्द्र व राज्य सरकारों के कर्मचारियों के तथा प्रतिरक्षा, फार्मास्यूटीकल्स, फर्टीलाईजर्स, बैंक, इन्श्योरेन्स आदि के महासंघ जो अपने उद्योंगों के मजदूरों के बहुसंख्यक हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्पोन्सरिंग कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन्स के भागीदार बने। इस प्रकार संयुक्त संघर्षों का मंच अब और अधिक व्यापक हो गया।

नब्बे के दंशक में तथा 21वीं सदी के पहले दशक के दौरान सरकार की LPG नीतियों के विरोध में स्पोन्सरिंग कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन्स ने आम हड़ताल सहित अनेक प्रकार की संघर्षात्मक कार्यवाहियाँ की हैं। 1991 से अभी तक 12 देशव्यापी हड़तालें की गयी और हर बार की हड़ताल में पिछली बार के मुकाबले भाग लेने वाले मजदूरों की तादाद और क्षेत्र का विस्तार कई गुणा होता गया है। देशव्यापी आम हड़ताल के अलावा बैंकों, इन्श्योरेन्स, जूट, वानिकीकरण, कोयला और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र आदि में होने वाली उद्योगवार हड़तालें अलग से हैं।

स्पोन्सरिंग कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन्स की पहल पर, किसानों, खेतिहर मजदूरों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं, वकीलों तथा अन्य व्यवसायों से जुड़े जन संगठनों से जुड़ी जनता को भी सरकार की घातक एवं जन विरोधी आर्थिक नीतियों के विरुद्ध संघर्ष में शामिल करके 1993 में नेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ मास ऑर्गेनाइज़ेशन (NPMO) गठित की गई।

इसके अलावा एन.टी.सी., इस्को एवं अन्य बीमार उद्यमों को पुर्नजीवित करने के सवाल पर आहुत संघर्षों में सम्बन्धित क्षेत्रों की लगभग सभी यूनियनों में शानदार एकता देखने को मिली है। स्पोन्सरिंग कमेटी और NPMO के घनीभूत प्रचार अभियान ने ऐसा वातावरण तैयार कर दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त संघर्षों से अलग रहने वाले इन्टक और बी.एम.एस. भी वैचारिक रुप से सरकार की LPG नीतियों के समर्थक होने के बावजूद भी सार्वजनिक रुप से LPG नीतियों के समर्थन में न तो स्वयं खड़े हो सके, और ना ही अपने साथ जुड़े संगठनों को इन नीतियों के विरुद्ध होने वाले देशव्यापी संघर्षों में शामिल होने से रोक सके। अंसगठित क्षेत्र के मजदूर भी बड़े पैमाने पर आम हड़तालों के दिनों

में, हड़ताल, सड़क जाम आदि में शामिल हुए हैं। इन सब कार्यवाहियों का ही प्रभाव है कि कॉंग्रेस, यूनाईटेड फ्रन्ट, भाजपा और फिर यू.पी.ए. की सरकारें इन नीतियों को उतनी तेजी से लागू नहीं कर पायी जिस तेजी से करना चाहती थी।

संघर्श में सम्पूर्ण एकता

सरकार की नीतियों के फलस्वरुप आर्थिक संकट और आम आदमी में बढ़ते असंतोष ने विरोध के मंच के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाया है। तेजी से बढ़ती महँगाई, आर्थिक संकट के चलते बढ़ी बेरोजगारी, और विनिवेश आदि के चलते इन्टक और बी.एम.एस. सहित देश के सभी ट्रेड यूनियनों को एक मंच पर आने के लिए मजबूर कर दिया है ताकि समूचे मजदूर वर्ग को लामबन्द करके पाँच सूत्रीय माँग–पत्र के लिए व्यापक संघर्ष हो सके। हम को इस अवसर का पूरा उपयोग करते हुए, मजदूर आन्दोलन की इस एकता के संदेश को जमीनी स्तर तक ले जाकर समूचे मजदूर वर्ग को सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष में उतारने का काम तेजी से करना चाहिए। उच्च स्तर पर बनी मजदूर नेताओं की एकता को जमीनी स्तर तक ले जाने का काम इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर एकता बनी है, उनके लिए संघर्ष तीव्रता से ही शासक वर्गों को जन विरोधी एंव घातक नीतियों को बदलने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जो कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिक आवश्यकता भी है।

इस व्यापक संयुक्त मंच के आह्वान पर 16 दिसम्बर 2009 को संसद पर विशाल धरना और 5 मार्च 2010 को देशव्यापी सत्याग्रह एवं जेल भरो का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 15 जुलाई 2010 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय स्तर का मजदूर सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें देशव्यापी आम हड़ताल का फैसला लिया जाना है। इसके अभियान को जमीनी स्तर पर ले जाने एवं अधिकाधिक मेहनतकशों को संयुक्त संघर्ष में उतारने के काम और संयुक्त मंच को विस्तारित करते हुए मजबूत करने की जिम्मेदारी के लिए सीटू को अग्रणी भूमिका अदा करनी होगी, ताकि आने वाले समय में भी इस संयुक्त मंच को संघर्षों में उतारा जा सके।

संयुक्त संघर्षों के अनुभव

सीटू स्थापना के बाद से ही देश के स्तर पर और उद्योग के स्तर पर संयुक्त संघर्ष आज की स्थायी आवश्यकता बन गया है, क्योंकि सीटू ने ही नीतिगत सवालों पर देशव्यापी आन्दोलन संगठित करने का रास्ता दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। संयुक्त संघर्ष के निर्माण की लगातार चलने वाली प्रक्रिया में ट्रेड यूनियन आन्दोलन के समक्ष नीतिगत मुद्दों पर सीटू की पहल ने भी मजदूर आन्दोलन को एकता के सूत्र में बाँधे रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

कोयला उद्योग के मजदूरों के लिए होने वाली छठे दौर की वेतन वार्ताओं के दौरान वर्ष 2000 में सीटू ने निर्णायक भूमिका अदा की है। जहाँ एक ओर कोयला उद्योग की शेष सभी यूनियनों ने अपने प्रबंधन समर्थक रवैऐ के चलते मजदूर विरोधी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, वहीं सीटू ने अकेले ही इस मजदूर विरोधी सहमति पत्र के विरोध में नवम्बर 2000 में तीन दिन की हड़ताल को आह्वान किया, जिसमें सभी यूनियनों के बहुसंख्यक मजदूरों ने भाग लिया और इस हड़ताल के दबाव में प्रबंधन को वह सहमति पत्र निरस्त करके पुनः वार्ता करनी पड़ी। सीटू की इस पहल ने बाद के दौर में कोयला उद्योग की सभी यूनियनों के लिए संयुक्त संघर्षों का रास्ता खोल दिया। अभी हाल ही में कोयला उद्योग के सभी ट्रेड यूनियन फेडरेशनों ने 27 मार्च 2010 को एक संयुक्त सम्मेलन करके सरकार के विनिवेश एवं काम के वाह्यीकरण के निर्णय के विरोध में 5–7 मई 2010 को तीन दिन की हड़ताल का आह्वान किया। परन्तु उसके बाद कोयला एवं वित्त मंत्री के साथ चली दो दौर की वार्ताओं में दोनों मंत्रियों के द्वारा विनिवेश एवं काम के वाह्यीकरण के कदम को वापस लेने से साफ मना करने के बावजूद भी तीन फेडरेशन के नेताओं ने हड़ताल से हाथ खींच लिया। ऐसी स्थिति में सीटू ने अकेले ही 5 मई 2010 को एक दिन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। कुछ फेडरेशन के नेताओं द्वारा हड़ताल से हाथ खींच लिए जाने के बावजूद भी, सीटू की सदस्यता से कहीं बहुत अधिक मजदूरों ने खुलकर हड़ताल में भाग लेकर, कोल इण्डिया लि० के विनिवेश करने के भारत सरकार के निर्णय के विरोध में अपना गुस्सा प्रकट किया है।

वर्तमान वेतन वार्ताओं के दौर में, कुछ ऐसी ही स्थिति स्टील

उद्योग में भी बन गयी। वर्ष 2009 में कुछ यूनियनों द्वारा प्रबंधक समर्थक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के विरोध में सीटू ने सार्वजनिक क्षेत्र के स्टील उद्यमों में दो दिन की हड़ताल का आह्वान किया, जिसमें मजदूरों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया और परिणामस्वरुप उस सहमति पत्र को मजदूरों के हित में बदला जा सका।

सार्वजनिक क्षेत्र में वर्तमान दौर की वेतन वार्ताओं के लिए सरकार द्वारा जारी 10 वर्षीय वेतन समझौते के दिशा–निर्देशों को बदलवाने के लिए CPSTU के नेतृत्व में सफल आन्दोलन चलाकर सरकार को दिशा–निर्देश बदलने के लिए मजबूर किया जा सका। परन्तु उद्योग स्तर पर वेतन वार्ताओं के दौरान कुछ यूनियनों ने प्रबंधन के दबाव में आकर 10 वर्षीय वेतन समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। लेकिन वार्ताओं के मंच पर अकेले रह कर सीटू ने अधिकांश सार्वजनिक उद्यमों में इन समझौतों पर हस्ताक्षर करने से स्वयं को अलग ही रखा है। सीटू मानता है कि 10 वर्षीय वेतन समझौते करने का अर्थ प्रबंधन के समक्ष घुटने टेकना और संयुक्त संघर्ष द्वारा हासिल उपलब्धि का आत्मसमर्पण करना है। अस्थायी थोड़े नुकसान के बावजूद सीटू ऐसे सैद्धान्तिक मसलों पर अलग रहने को प्राथमिक समझती है, और पूरा विश्वास है कि ऐसी यूनियनें समय आने पर अपनी गलती का एहसास अवश्य करेगीं।

मजदूर आन्दोलन के समक्ष आने वाले अहम् सवालों पर ऐसा सैद्धान्तिक दृढ़ता के बिना और इन सिद्धान्तों पर चलकर संघर्ष किए बिना मजदूर आन्दोलन को ठीक रास्ते पर नहीं रखा जा सकता है। और गैर–सैद्धान्तिक एकता को भी बनाए रखना संभव नहीं होता।

स्वतंत्र संघर्षों के बारे में

ऐसे अवसर भी आए हैं जब मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए सीटू को अकेले ही संघर्ष करना पड़ा है। वर्ष 1971 में जब काँग्रेस सरकार ने फैमिली पेंशन स्कीम लागू की, तो सीटू ने "फैमिली पेंशन स्कीम – एक धोखा" नाम से एक बुकलेट प्रकाशित की जिसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। अन्य केन्द्रीय मजदूर संघों ने इस पेंशन स्कीम का स्वागत किया, जबकि सीटू ने खुलासा किया कि इस स्कीम के अर्न्तगत मजदूरों से कटौती अधिक होगी और पेंशन के रुप में भुगतान बहुत ही कम होगा। परिणामस्वरुप 1995 में जब इस फैमिली पेंशन स्कीम

के स्थान पर एम्प्लॉईज पेंशन स्कीम लागू की गयी तो सरकार के पास पुरानी पेंशन स्कीम का रु० 14000 करोड़ शेष था।

जब 1995 में सरकार ने एम्प्लॉईज पेंशन स्कीम लागू की तो सीटू ने इस आधार पर पुनः विरोध किया कि मजदूर इस पेंशन स्कीम में जितना धन देंगें उसके मुकाबले पेंशन के रुप में उसका एक अंश मात्र ही प्राप्त कर सकेगें। सीटू ने अपने प्रकाशन द्वारा विस्तारित गणना प्रस्तुत करते हुए बताया कि सरकार द्वारा प्रस्तुत स्कीम टिक नहीं सकेगी और मजदूर को भारी हानि होगी। सीटू ने माँग की कि प्रस्तावित स्कीम को समाप्त करके पी.एफ. और ग्रेच्युटी से अलग सेवानिवृत्ति के तीसरे लाभ के रुप में पेंशन स्कीम लायी जाए। जबकि अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने सरकार का खुला समर्थन किया और सीटू को अकेले ही संघर्ष करना पड़ा। सीटू ने कुछ ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया, जिसमें मजदूरों का भारी समर्थन हासिल हुआ। आज मजदूरों को इस पेंशन स्कीम के तहत प्राप्त होने वाला मामूली से लाभ से यंह सिद्ध हो जाता है कि स्कीम लागू होते समय सीटू ने जो आशंका जाहिर की थी वह पूरी तरह से ठीक ही निकली है। इसके ऊपर सीटू को छोड़कर शेष सभी केन्द्रीय श्रम संघों के बिना शर्त समर्थन से पास हुए कानून में संशोधन करके केन्द्र सरकार ने एक तरफा तरीके से मजदूरों को देय हितलाभों में कटौतियाँ कर दी है। स्टील वर्कर्स फेडरेशन ने स्कीम की तमाम कमियों को लेकर उच्चतम न्यायालय में रिट दायर की परन्तु सफलता नहीं मिल सकी। काफी लम्बे अनुभव के बाद आज सभी केन्द्रीय श्रम संघ इस पेंशन स्कीम की आलोचना कर रहे हैं।

सांगठनिक दृष्टिकोण

मेहनतकशों के एक क्रान्तिकारी संगठन के पास एक क्रान्तिकारी नज़रिए का होना अति आवश्यक है। इस नज़रिए का एक बुनियादी आधार यह है कि संगठन के सभी स्तरों से पहल करते हुए सभी क्षेत्रों में संघर्षों की कार्यवाहियों का विस्तार समानान्तर रुप से किया जाए। सीटू के गठन के बाद पहल करके अलग–अलग क्षेत्रों एव उद्योगों में उद्योगवार फेडरेशनों का गठन किया गया।

सीटू द्वारा गठित पहला फेडरेशन था–ऑल इण्डिया प्लान्टेशन

वर्कर्स फेडरेशन। दिसम्बर 1971 में एक अखिल भारतीय सम्मेलन दार्जिलिंग में बुलाया गया जिसका उद्घाटन का० बी.टी. रणदिवे ने किया। उसके बाद के दौर में वाटर ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया का गठन किया गया जो पोर्ट एण्ड डॉक तथा सीमैन्स का प्रतिनिधित्व करता है। 1973 में ऑल इण्डिया रोड ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन ऑफ इण्डिया, 1982 में स्टील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया, 1982 में ऑल इण्डिया कोल वर्कर्स फेडरेशन, कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया, इलेक्ट्रीसिटी एम्पलॉईज फेडरेशन ऑफ इण्डिया, ऑल इण्डिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स और ऑल इण्डिया बीड़ी वर्कर्स फेडरेशन आदि का गठन हुआ है।

फेडरेशन ऑफ मेडीकल एण्ड रिप्रेन्जेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (FMRAI) एक और अखिल भारतीय फेडरेशन है जो सम्बन्धित क्षेत्र में कार्यरत सीटू सम्बद्ध यूनियनों के साथ–साथ कुछ स्वतंत्र यूनियनों को मिलाकर बनाया गया। समय व्यतीत होने के साथ FMRAI से जुड़ी लगभग सभी यूनियनें सीटू से सम्बद्ध हो चुकी हैं।

सीटू ने कुछ सैक्टरों में कार्यरत विभिन्न केन्द्रीय श्रम संघों से सम्बद्ध यूनियनों को शामिल करते हुए उद्योगवार फैडरेशनों के गठन भी पहल की है। फर्टीलाइज़र्स वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया को सार्वजनिक क्षेत्र के फर्टीलाइज़ उद्योगों की ऐसी यूनियनों को मिलाकर बनाया गया, जो विभिन्न केन्द्रीय श्रम संघों से सम्बद्ध हैं। यह पिछले दशकों से उद्योग मजदूरों और उद्योग के हितों की रक्षा की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाते हुए बखूबी काम करता रहा है। परन्तु अधिकांश प्लान्टों के बीमार होकर बन्द हो जाने के कारण अब यह फैडरेशन निष्क्रिय हो गया है। पेट्रोलियम एण्ड नेचुरल गैस वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया का गठन, विभिन्न राजनैतिक विचारधाराओं की यूनियनों और पेट्रोलियम सैक्टर में कार्यरत स्वतंत्र यूनियनों को शामिल करके बनाया गया जिसका नेतृत्व सीटू के नेता अन्य के साथ मिलकर कर रहे हैं।

ऑल इण्डिया फिशर्स एण्ड फिशरीज वर्कर्स फैडरेशन अभी हाल ही में गठित फैडरेशन है, ताकि मछुआरों और मत्स्य पालन उद्योंगों में कार्यरत अलग–अलग राज्यों के मजदूरों के आन्दोलन को सीटू और ऑल इण्डिया किसान सभा मिलकर राष्ट्रव्यापी बनाकर संघर्षों का सफलतापूर्वक संचालन कर सकें। सभी राज्य कमेटियों को कहा गया है

कि बड़ी संख्या में मौजूद मछुआरों और मत्स्य पालन उद्योगों में कार्यरत मजदूरों को इस फैडरेशन के तहत संगठित किया जाय। और समाज के सर्वाधिक शोषित इन मजदूरों के अखिल भारतीय आन्दोलन के विकसित होने की काफी संभावनाएं मौजूद हैं।

उपरोक्त क्षेत्रों के अलावा फूड कोऑपरेशन ऑफ इण्डिया तथा आशा (ASHA) एवं मिड डे मील से जुड़े मजदूरों की एक समन्वय समिति बनाने के प्रयास जारी हैं।

कामगार महिलाऐं

सीटू के नज़रिए में विशेष ध्यान देकर कामगार महिलाओं को मजदूर आन्दोलन के साथ जोड़ने का काम सबसे महत्वपूर्ण वर्गीय काम है। कामगार महिलाओं को संगठित करके मजदूर आन्दोलन के साथ जोड़कर नेतृत्व में लाने का काम के लिए सीटू ने भारत के मजदूर आन्दोलन के इतिहास में सबसे अग्रणी भूमिका अदा की है। वर्ष 1979 में कामगार महिलाओं का एक अखिल भारतीय सम्मेलन करके ऑल इण्डिया कोऑर्डीनेशन कमेटी ऑफ वर्किंग वूमेन का गठन करने की सर्वप्रथम पहल की है। उसके बाद अन्य श्रम संघों ने भी ऐसी शुरुआत की है। हमारी इस पहल से ट्रेड यूनियनों में महिलाओं की सदस्यता और आन्दोलनों एवं संघर्षों के आयोजनों व संचालन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी में जबरदस्त वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में सीटू की कुल सदस्यता में महिलाओं की सदस्यता 25 प्रतिशत से भी कहीं अधिक है

महिलाओं में विद्यमान बेहतर सांगठनिक एवं सक्रियता की क्षमता के चलते महिलाओं का मजदूर आन्दोलन पर छा जाना उनके नेतृत्व करने की क्षमता दर्शाता है। अभी हाल ही में सीटू की पहल पर नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के धरने में 20 हजार आंगनवाड़ी कर्मचारियों और 7 हजार आशाओं (ASHAs) जमा होना इसका सबसे बड़ा सबूत कहा जा सकता है। सीटू ने अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस की शतवार्षिकी पूरे साल मनाने का निर्णय लिया है। इस अवसर का उपयोग महिलाओं की विशेष समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए किया जाना चाहिए ताकि ट्रेड यूनियन आन्दोलन के लिए सीटू के सांगठनिक ढ़ाँचे में महिलाओं को निर्णय लेने में अधिक सक्रिय किया जा सके।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बारे में

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ट्रेड यूनियनों में संगठित करने मामले में भी सीटू ने अग्रणी भूमिका अदा की है। सीटू की वर्तमान सदस्यता 50 प्रतिशत से अधिक असंगठित क्षेत्र से है, जिसमें प्रमुख रुप से बीड़ी, भवन निर्माण, सिर पर बोझा ढोने वाले, ईंट भट्टा उद्योग, जंगलात, काजू उद्योग, प्राईवेट ट्रान्सपोर्ट, हॉकर्स, रेहड़ी पटरी आदि उद्योगों में कार्यरत मजदूर हैं। सीटू ने पूरे देश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कई संघर्षों का संचालन किया है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए समग्र कानून और सामाजिक सुरक्षा का कानून बनाने के लिए देशव्यापी अभियान और आन्दोलन चलाकर एक दिन की सफल हड़ताल करके असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए समग्र कानून और सामाजिक सुरक्षा का कानून बनाने की माँग की है।

भुवनेश्वर दस्तावेज

संगठन में काफी लम्बी चर्चा के बाद सीटू ने भुवनेश्वर में आयोजित अपनी कार्य समिति की बैठक में संगठन पर एक दस्तावेज स्वीकार किया जिसमें, सीटू की कार्य प्रणाली में विद्यमान खामियों को आत्म आलोचनात्मक तरीके से रेखांकित किया है। इसे अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों के साथ–साथ अपने अन्तिम लक्ष्य–समाजवादी समाज की स्थापना को प्राप्त करने के साथ जोड़ने का प्रभावशाली प्रयास कहा जा सकता है। इस दस्तावेज में ट्रेड यूनियन आन्दोलन में व्याप्त गलत मजदूर विरोधी रुझानों को रेखांकित किया है और रोजमर्रा की कार्यवाहियों में इन गलत रुझानों के खिलाफ लड़ने पर जोर दिया गया है। यह दस्तावेज ट्रेड यूनियनों में जनवादी कार्यप्रणाली पर जोर देते हुए यूनियनों के सभी सदस्यों और कार्यकर्ताओं को रोजमर्रा होने वाली ट्रेड यूनियन गतिविधियों में सक्रिय करने पर जोर देता है। कामगार महिलाओं के मामले में कहा गया है कि महिलाओं की विशेष समस्याऐं ट्रेड यूनियन के मुद्दों की तरह ली जाएं। यह दस्तावेज एक उद्योग में एक यूनियन और पूरे देश में एक ट्रेड यूनियन केन्द्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए ट्रेड यूनियनों का कन्फेडरेशन बनाने पर जोर देता है।

सर्वहारा का मजबूत अर्न्तराष्ट्रीयतावाद

भारतीय मजदूर आन्दोलन पूँजीवादी शोषण के विरुद्ध दुनियाभर के मेहनतकशों के संघर्षों का ही एक हिस्सा है। सीटू ने अपने स्थापना सम्मेलन में ही मेहनतकशों के अर्न्तराष्ट्रीय भाईचारे की पुरजोर वकालत की थी। और उसने वर्ल्ड फैडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स (WFTU) के साथ दोस्ताना ताल्लुकात विकसित किए हैं। जब अस्सी के दशक में WFTU ने मजदूर वर्ग की विचारधारा और साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष को त्याग दिया तो सीटू ने WFTU के विरुद्ध अपनी आवाज बुलन्द की। WFTU ने हवाना काँग्रेस के बाद अपनी साम्राज्यवाद और वर्ग संघर्ष की नीति पर पुनः जोर दिया तो सीटू ने WFTU में आए बदलाव का स्वागत करते हुए उसके साथ दोस्ताना ताल्लुकात को पुनः मजबूत किया और उसके कई संगठनों जैसे TUI-Energy, TUI- Steel, TUI-Public Services आदि में नेतृत्वकारी भूमिक अदा की है।

सीटू ने आस्ट्रेलिया की ट्रेड यूनियन ACTU, दक्षिण कोरिया KCTU की दक्षिण अफ्रीका की COSATU ब्राजील की CUT फिलीपीन्स की KMU, जापान की जेनोरियन, फ्रान्स की CGT के साथ दोस्ताना ताल्लुकात विकसित किए हैं, जो कि WFTU से अलग हैं। सीटू सदर्न इनिशिएटिव ऑन ग्लोबलाईज़ेशन एण्ड ट्रेड यूनियन राईटस् (SIGTUR) जो कि साम्राज्यवाद और वैश्वीकरण के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है। सीटू कोलकाता एवं कोचीन में SIGTUR के दो सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न करा चुकी है। सीटू अर्न्तराष्ट्रीय ऊर्जा और खदान संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। हालाँकि इन्टरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फैडरेशन (ITUC) साम्राज्यवाद और वैश्वीकरण के खिलाफ लड़ता नहीं है फिर भी उससे जुड़ी साम्राज्यवाद और वैश्वीकरण के खिलाफ लड़ने वाली यूनियनों के साथ सीटू के काफी गहरे सम्बन्ध हैं, और उनके साथ प्रतिनिधियों एवं विचार विमर्श का आदान प्रदान बनाए हुए है। सीटू के अखिल भारतीय सम्मेलन में अधिकाधिक अर्न्तराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। सीटू ने सभी चारों महाद्वीपों के 40 से अधिक देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध हैं। सीटू के प्रतिनिधि अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलनों में भाग लेकर मजदूर आन्दोलन के लिए नेतृत्वकारी भूमिका अदा करते हुए, उन सभी संगठनों के साथ बेहतर सम्बन्ध

विकसित कर रही है, जो साम्राज्यवाद और वैश्वीकरण की नवउदारवादी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं।

उज्जवल भविश्य पर नजर

चण्डीगढ़ में आयोजित सीटू के 13वें सम्मेलन में अगले सम्मेलन तक सीटू की सदस्यता को 75 लाख करने का लिया फैसला हमारे समक्ष एक बड़ी चुनौती है। हमें असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर अपना ध्यान अधिक केन्द्रित करना होगा। उनका काफी बड़ा हिस्सा अभी भी मजदूर आन्दोलन के बाहर है। हमें विशेष रुप से अपना ध्यान ठेका मजदूरों पर केन्द्रित करना होगा जिनकी तादाद प्रत्येक उद्योग में दिनों–दिन लगातार बढ़ती ही जा रही है। हमें अपनी गतिविधियों को अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र जैसे वित्त, ऊर्जा, यातायात और संचार आदि में तेज करना होगा क्योंकि इन क्षेत्रों का पूँजीवाद के विरुद्ध संघर्ष बहुत मायने रखता है।

जब तक कमजोरी वाले क्षेत्र अपने संगठन और संघर्ष क्षमता को मजबूत नहीं करते तब तक हम पूँजीवाद के हमलों का प्रभावशाली जबाव नहीं दे सकते। हम यदि कमजोर क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ते हैं तो अपने मजबूत क्षेत्र के अपना सम्मान को भी नहीं बचा पाऐगें। अगर हम अपना ध्यान केन्द्रित करके स्थानीय संघर्षों को आगे बढ़ाऐं तो बकायदा तमाम संभावनाएं मौजूद हैं।

हमें कामगार महिलाओं के बीच अपना काम बढ़ाकर उन्हे अधिकाधिक रोजमर्रा की ट्रेड यूनियन कार्यवाहियों में शामिल करना होगा। इस बात की पूरी संभावना है कि अगले तीन वर्षों में हम अपनी सदस्यता में महिलाओं की सदस्यता को 30 प्रतिशत से अधिक कर लें।

मजदूर आन्दोलन में अपनी दखल देने की क्षमता में बढ़ोत्तरी करने के लिए हमें अपने सांगठनिक ढ़ाँचे को मजबूत करते हुए विस्तार करने का काम अत्यन्त आवश्यक है। भुवनेश्वर दस्तावेज के दिशा–निर्देशों पर विशेष ध्यान देकर लागू करने की आवश्यकता है। अपनी सभी संस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करके मजदूर वर्ग के मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अपनी संघर्ष क्षमता से ही तेजी के साथ विस्तार संभव है। हमें मजदूर वर्ग में मौजूद एकता और संयुक्त संघर्ष की सभी संभावनाओं का पूरा

उपयोग करना होगा।

हमें अपने नेतृत्व और कार्यकर्ताओं में विचारधारात्मक एवं राज़नैतिक समझदारी विकसित करने पर विशेष ध्यान देने की तुरन्त आवश्यकता है। और इस वास्ते हमें अपने 13वें सम्मेलन में लिए गए फैसलों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए इन फैंसलों को पूरी समझदारी और तेजी के साथ लागू करना होगा। और सीटू की स्थापना की 40वीं वर्षगाँठ मनाते हुए 13वें सम्मेलन में लिए गए फैसले के अनुसार पूरे वर्ष शिक्षा के कार्यक्रमों को पूरी समझदारी और गम्भीरता से लागू करना होगा।

मजदूर आन्दोलन में मौजूद भ्रष्ट विचारधाराओं और कार्यविधियों के विरुद्ध लगातार संघर्ष करते हुए भारतीय स्तर पर सही विचारधारा को स्थापित करने के लिए काम करना होगा।

आज जब पूँजीवाद मजदूर वर्ग को झूठे सपने दिखा रहा है, तो हमें मजूदरों के बीच समाजवादी विचारों का प्रचार करते हुए स्थापित करना होगा। कां० पी राममूर्ति स्मारक ट्रेड यूनियन स्कूल की स्थापना के काम को जल्द से जल्द पूरा करना होगा, जिसके लिए सीटू को जनता के पूरे सहयोग की आवश्यकता होगी।

हिन्दुस्तान में मजदूर वर्ग और मजदूर आन्दोलन को क्रान्तिकारी सोच के साथ आगे ले जाना होगा। और इसके लिए सीटू एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।

आओ चलो, चलें उज्जवल भविष्य की ओर

मजदूर वर्ग और हिन्दुस्तान की जनता यदि संगठित और एकताबद्ध हो तो वह स्वयं अपनी मंज़िल तय कर सकती हैं। उज्जवल भविष्य के वास्ते, विचारधारा से लैस हो कर परिवर्तन करने के लिए संघर्ष को कटिबद्ध हों।

सी.आई.टी.यू. जिन्दाबाद!

30 मई 2010